



राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)

परामर्शी कार्यशाला

कृषि विस्तार प्रणाली का डिजिटलीकरण



मैनेज ने 15 अप्रैल 2023 को भारत में कृषि विस्तार प्रणाली के डिजिटलीकरण पर एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य देश के 10 चुनिंदा राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से कृषि विस्तार के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को लागू करने की योजना को संवेदनशील बनाना और तैयार करना था। कार्यशाला की अध्यक्षता श्री सैमुअल प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव (विस्तार), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने की और इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक

प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसका प्रतिनिधित्व करने आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों और टीम के सदस्यों सहयोगी संगठन डिजिटल ग्रीन, मैनेज, टेकडी और ग्राम वाणी ने किया।

प्रस्तावित राष्ट्रीय मंच स्थानीय संदर्भ के साथ कृषक समुदाय को ऑडियो/वीडियो उपकरण के माध्यम से संबंधित जानकारी का समय पर प्रवाह प्रदान करेगा

Continued on P 6

1

भारत में कृषि विस्तार प्रणाली के डिजिटलीकरण पर परामर्शी कार्यशाला

2

महानिदेशक का संदेश: भारत में अग्रणी कृषि-व्यवसाय प्रबंधन शिक्षा

3

मन की बात का जैविक/प्राकृतिक खेती और कृषि स्टार्टअप पर प्रभाव

5

विस्तार वितरण में केविके और एटीएमए पर राष्ट्रीय परामर्श

7

मध्य प्रदेश में डीएईएसआई के प्रभावी कार्यान्वयन पर कार्यशाला

8

इंटरनेशिप कार्यक्रम: बागवानी छात्रों के लिए कृषि स्टार्टअप

9

कार्यशाला: प्रतिस्पर्धा कानून और सार्वजनिक खरीद

10

नए संकाय सदस्य

भारत में अग्रणी कृषि-व्यवसाय प्रबंधन शिक्षा



मैनेज ने वर्ष 1996 में स्व-वित्त आधार पर प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (कृषि-व्यवसाय प्रबंधन) कार्यक्रम की शुरुआत की है तब से, पीजीडीएम (एबीएम) कार्यक्रम कृषि-व्यवसाय शिक्षा में एक मानक और बेंचमार्क बन गया है और देश के कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों ने इसी तरह के कार्यक्रम शुरू करने में मैनेज का मार्ग अपनाया है। कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से अब तक, मैनेज ने 27 बैचों में कृषि-व्यवसाय उद्योग के लिए 1228 तकनीकी-प्रबंधकों का उत्पादन किया है। हम, मैनेज में, गर्व महसूस करते हैं कि हमारे कई छात्र अब उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अग्रणी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कृषि-व्यवसाय कंपनियों में शीर्ष प्रबंधकीय पदों पर हैं।

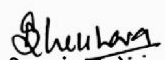
मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार ने 26 अगस्त 2022 को मैनेज में आयोजित छठे दीक्षांत समारोह-2022 के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में घोषणा की कि कृषि व्यवसाय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 2023 से पीजीडीएम (एबीएम) कार्यक्रम में सीटों की संख्या 66 से बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी। ताकि देश में कृषि व्यवसाय प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और कार्यक्रम का लाभ अनेक विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सके। तदनुसार, बैच 2023-25 से पीजीडीएम (एबीएम) में सीटों की संख्या प्रति वर्ष 100 तक बढ़ा दी गई है और इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है।

कार्यक्रम को वर्तमान बनाने और विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में इसमें नए नवाचार पेश किए गए हैं। ये नए नवाचार शिक्षण अध्यापन, उद्योग इंटरफेस, चयन प्रक्रिया, प्लेसमेंट आदि तक फैले हुए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2023 से, "स्टूडेंट एक्सपोजर प्रोग्राम" के लिए नॉटिंघम विश्वविद्यालय, मलेशिया के साथ एक समझौता जापान पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पीजीडीएम (एबीएम) के छात्र इस कार्यक्रम के तहत 3 से 18 जुलाई, 2023 तक नॉटिंघम विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे जहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय कृषि-व्यवसाय की गतिशीलता से अवगत कराया जाएगा।

कार्यक्रम एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा मान्यता प्राप्त है और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) से समकक्ष है। एग्रीकल्चर टुडे की हालिया रैंकिंग के अनुसार, मैनेज पीजीडीएम (एबीएम) को आईआईएमए और आईआईएमएल के बाद देश में नंबर 3 सेक्टरल बी-स्कूल का दर्जा दिया गया है। अपनी छवि के अनुरूप, कार्यक्रम शुरू से ही 100% प्लेसमेंट दे रहा है और सीटीसी साल-दर-साल बढ़ती जा रही है। हाल ही में समाप्त हुए बैच 2021-23 के लिए, औसत सीटीसी रु. 12.15 लाख, उच्चतम 20 लाख है अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट के लिए सीटीसी की पेशकश रु. 45 लाख है।

मैनेज कृषि-व्यवसाय क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए पीजीडीएम (एबीएम) की गुणवत्ता और मानक में सुधार के लिए हमेशा कड़े प्रयास करता है और भारत को कृषि में वैश्विक नेता बनाए रखने के लिए देश में अग्रणी कृषि व्यवसाय प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है।

"पीजीडीएम (एबीएम) कार्यक्रम कृषि-व्यवसाय शिक्षा में एक मानक और बेंचमार्क बन गया है और देश के कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों ने इसी तरह के कार्यक्रम शुरू करने में मैनेज का मार्ग अपनाया है"


डॉ. पी. चंद्रा शेखरा
महानिदेशक

मन की बात का जैविक/प्राकृतिक खेती और कृषि-स्टार्टअप पर प्रभाव



मैनेज ने 27 अप्रैल 2023 को मैनेज में आयोजित एक समारोह में दो शोध लेख जारी किए, जिनमें भारत में जैविक/प्राकृतिक खेती और कृषि-स्टार्टअप पर "मन की बात" कार्यक्रम के प्रभाव की जांच की गई। ये लेख जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट (जनवरी-जून 2023 अंक) में प्रकाशित हुए थे, जो मैनेज द्वारा प्रकाशित एक अर्ध-वार्षिक पत्रिका है।

पहला लेख "जैविक और प्राकृतिक खेती पर मन की बात कार्यक्रम के प्रभाव पर अध्ययन" एक अखिल भारतीय अध्ययन

था जिसने किसानों और उपभोक्ताओं के बीच जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर "मन की बात" के प्रभाव की जांच की। अध्ययन में पाया गया कि इस कार्यक्रम का भारत में जैविक/प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कार्यक्रम ने उन किसानों की संख्या बढ़ाने में मदद की है जो जैविक खेती के तरीके अपना रहे हैं और उपभोक्ताओं के बीच जैविक उत्पादों की मांग में भी वृद्धि हुई है।

दूसरा लेख "भारत में कृषि-स्टार्टअप पर केस स्टडीज: मन की बात से प्रेरणा, नवाचार और प्रभाव" पांच केस अध्ययनों के

माध्यम से भारत में कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर "मन की बात" के प्रभाव पर केंद्रित है। अध्ययन में पाया गया कि कार्यक्रम ने स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को उजागर करके और नए उद्यमियों को प्रेरित करके भारत में कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम ने स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया है और उन्हें संभावित निवेशकों और ग्राहकों से जोड़ने में मदद की है।

समारोह के दौरान, शोध लेखों के लेखकों ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिन्हें दर्शकों ने बहुत रुचि के साथ स्वीकार किया। लेख मैनेज वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं, और वे भारत में जैविक/प्राकृतिक खेती और कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर "मन की बात" के प्रभाव पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

ये शोध लेख कृषि विकास पर मन की बात कार्यक्रम के प्रभाव में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और इन क्षेत्रों में नीति निर्माताओं, किसानों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं।



मन की बात का जैविक/प्राकृतिक खेती और कृषि-स्टार्टअप पर प्रभाव

जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर मन की बात कार्यक्रम के प्रभाव पर अध्ययन

सारांश

अध्ययन का उद्देश्य तीन हितधारकों अर्थात केवीके पदाधिकारियों, किसानों और उपभोक्ताओं पर मन की बात कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करना है। इस पेपर का उद्देश्य किसानों द्वारा जागरूकता, भागीदारी, ट्रिकलडाउन प्रभाव के साथ-साथ प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की सीमा का विश्लेषण करना है। अध्ययन में देश भर के 10 अटारी क्षेत्रों को कवर करते हुए जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में पर्याप्त भागीदारी के आधार पर चयनित केवीके को शामिल किया गया। जिन किसानों और उपभोक्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम में शामिल जैविक/प्राकृतिक खेती के एपिसोड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है, उन्हें चयनित केवीके द्वारा यादृच्छिक रूप से चुना गया था। मुख्य निष्कर्ष यह है कि लगभग 92 प्रतिशत किसान खेती के तरीकों को बदलने में रुचि रखते थे, 82 प्रतिशत ने आगे जानने के लिए अनुवर्ती यात्रा की, 78 प्रतिशत ने अन्य साथी किसानों के साथ जानकारी साझा की और लगभग 78 प्रतिशत ने जानकारी साझा की। जैविक/प्राकृतिक खेती पर सीधे प्रधानमंत्री की बात सुनकर किसान खुश हुए। जबकि करीब 88 फीसदी उपभोक्ताओं में जागरूकता का स्तर बढ़ा, और मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद 63 प्रतिशत लोग जैविक/प्राकृतिक खेती उत्पादों के प्रति आश्वस्त हुए। अधिकांश केवीके (88%) ने परिसर और परिसर के बाहर दोनों जगह 1 से 10 मन की बात कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मन की बात कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए व्हाट्सएप और मोबाइल एसएमएस का उपयोग किया गया और जैविक/प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को समर्थन देने के लिए केवीके ने, विभिन्न अनुवर्ती गतिविधियां शुरू की हैं।

लेखक: एन. बालासुब्रमणि, पी.चंद्रा शेखरा, सैमुअल प्रवीण कुमार, सी. श्रीलक्ष्मी और एस.के. जमनाल.

भारत में कृषि-स्टार्टअप पर केस स्टडीज: मन की बात से प्रेरणा, नवाचार और प्रभाव

सारांश

नवाचार सफल स्टार्टअप की कुंजी है। स्टार्टअप कृषि-खाद्य प्रणालियों की कई गतिविधियों में सुधार द्वारा समर्थित प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित कर रहे हैं। स्टार्टअप के लिए एक प्रमुख समर्थन स्तंभ के रूप में, राष्ट्रीय स्टार्टअप नीति, कार्यक्रमों और पीएम की 'मन की बात' का भी उद्यमियों पर नवाचार को क्रियान्वित करने के लिए प्रभाव पड़ा। इस अध्ययन में 5 स्टार्टअप को शामिल किया गया है, जैसे आत्मा लेदर, सोनारपुर, पश्चिम बंगाल, बारीफलो लैब्स, भुवनेश्वर, ओडिशा, ट्राइब गोन, अमरावती, महाराष्ट्र, पशुपाला कॉम, बेंगलुरु, कर्नाटक, इको एग्रीप्रेनर्स, देवनागरे, कर्नाटक इससे प्रभावित हैं। चयनित स्टार्टअप नवाचारों और प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं जैसे: केले का चमड़ा, जलीय कृषि के लिए एआई-आईओटी रोबोटिक वातन उपकरण, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला के साथ जंगली शहद और आदिवासी उद्यमियों का निर्माण, पशुधन व्यापार के लिए मूल्य श्रृंखला समर्थन वाला ऑनलाइन बाजार और पर्यावरण-अवशेष कम चावल को शामिल किया गया है ताकि इस विचार से लेकर कृषि-सत्रअप पर केस अध्ययन में नवाचार, कार्यान्वयन तक की विकसित प्रक्रिया, हितधारक की भागीदारी, ऊष्मायन समर्थन और किसानों और अन्य हितधारकों के बीच स्टार्टअप के प्रभाव की उभरती प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके।

लेखक: सरवणन राज, युवराज आत्मकुरी, अमित आर. काले, प्रवीण एच.जे., सौरभ कुमार और अंजू अब्राहम

विस्तार वितरण में केवीके और एटीएमए को मजबूत करना



मैनेज ने 24 और 25 अप्रैल, 2023 को विस्तार वितरण में केवीके और एटीएमए पर दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श की मेजबानी की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समेति, ईईआई, आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार निदेशालय के 25 वरिष्ठ विस्तार प्रबंधन विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित विस्तार पेशेवर जिन्होंने देश में कृषि विस्तार में योगदान दिया है, की भागीदारी के साथ किया गया था।



परामर्श का उद्देश्य विशेष रूप से केवीके और एटीएमए के माध्यम से कृषि विस्तार सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए एक रोडमैप विकसित करना था। परामर्श ने कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार के लिए नवीन रणनीतियों पर चर्चा करने और विकसित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाया। तकनीकी सत्रों और चर्चाओं का उद्देश्य नए विचारों को उत्पन्न करना था जिन्हें किसानों को सेवाएं

प्रदान करने में केवीके और एटीएमए प्रणालियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लागू किया जा सकता है।

तकनीकी सत्र और खुली चर्चाएं अनुभवों को साझा करने और विस्तार सुधारों, नीति वकालत, पीपीपी को बढ़ावा देने, उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग, क्षमता निर्माण और केवीके और एटीएमए प्रणालियों को मजबूत करने के प्रयासों के अभिसरण के लिए भविष्य की रणनीतियों को आकार देने पर केंद्रित थीं। परामर्श में किसानों के मुद्दों को कैसे संबोधित किया जाए और केवीके और एटीएमए के माध्यम से भारत सरकार के चल रहे कार्यक्रमों और योजनाओं का समर्थन कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की गई। परामर्श के परिणाम देश में कृषि विस्तार को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों में योगदान देंगे।

कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. सरवणन राज, निदेशक (कृषि विस्तार), और डॉ. एन. बालासुब्रमणि, निदेशक (एसए एंड सीसीए), मैनेज द्वारा किया गया।



भारत में कृषि विस्तार प्रणाली का डिजिटलीकरण



और भाषा; विस्तार पेशेवरों की क्षमता निर्माण; और कृषि विस्तार प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक डिजिटलीकृत फीडबैक तंत्र विकसित करना। राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो अभिसरण के वास्तविक मॉडल पर काम करता है। इसके तीन महत्वपूर्ण घटक हैं।

1. सामग्री प्रबंधन प्रणाली जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सरकारी योजनाओं पर ऑडियो/विजुअल और संदर्भ पठन सामग्री के घटक हैं।
2. एक स्व-गति, दिलचस्प उपयोग में आसान मॉड्यूल के माध्यम से फ्रंटलाइन विस्तार कार्यकर्ताओं की प्रबंधन प्रणाली सीखना।
3. फीडबैक प्रबंधन प्रणाली जो समय पर फीडबैक एकत्र करने में मदद करती है जिसका विस्तार प्रणाली के लिए सामग्री और क्षमता को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर विश्लेषण किया जा सकता है।

कार्यशाला के दौरान, प्रतिभागियों को देश के चुनिंदा 10 राज्यों में समय सीमा के साथ पहल के कार्यान्वयन के लिए विचार-मंथन करने और रणनीति बनाने के लिए चार कार्य समूहों - क्षमता समूह प्रशिक्षण समूह आईटी समूह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) समूह में विभाजित किया गया था।

डॉ. श्रीकांत, वरिष्ठ वैज्ञानिक (डिजिटल कृषि), आईसीआरआईएसएटी, श्री हनुमंत कौंडीबा ज़ेंडगे आईएस, सहायक सचिव, तेलंगाना, डॉ. शेख एन. मीरा, निदेशक (एटीएआरआई), श्री कृष्णन, एमडी, डिजिटल ग्रीन, श्री आनंद, मिशन लीडर @ Apurva.ai मुख्य मंच सलाहकार, एकस्टेप फाउंडेशन में सोशल थिंकिंग, और डॉ. के. कृष्णा रेड्डी, निदेशक (आईसीटी), मैनेजने भाग लिया और प्रतिनिधियों को संबोधित किया और उन्हें कृषि विस्तार और डिजिटल अनुप्रयोगों में नवीनतम विकास के बारे में जागरूक किया।

एमए एंड एफडब्ल्यू और एकस्टेप फाउंडेशन ने एआई के माध्यम से कृषि विस्तार को बिजली देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

परामर्शी कार्यशाला के मौके पर, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एकस्टेप फाउंडेशन, बेंगलुरु श्री सैमुअल प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव (विस्तार), एमए एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार और अपूर्वा एआई, एकस्टेप फाउंडेशन में सामाजिक सोच के लिए मुख्य प्लेटफॉर्म सलाहकार एवं श्री आनंद, मिशन लीडर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एमओयू का उद्देश्य भारत में कृषि विस्तार प्रणाली को बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का लाभ उठाना है। कृषि में प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व के साथ, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और एकस्टेप फाउंडेशन के बीच सहयोग किसानों को उनकी कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए प्रासंगिक जानकारी, नवीन उपकरण और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करेगा।



मध्य प्रदेश में देसी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन



मैनेज ने 19.04.2023 को मध्य प्रदेश में देसी (इनपुट डीलर्स के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला एसआईआईटी भोपाल में आयोजित की गई थी और इसमें फैसिलिटेटर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स सहित 42 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

कार्यशाला का उद्देश्य मध्य प्रदेश में डीआईएसआई कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा करना और इनपुट डीलर्स के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन की गुणवत्ता में सुधार के तरीकों की पहचान करना था। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को इनपुट की बेहतर डिलीवरी और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए इनपुट डीलर्स को व्यापक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है।

कार्यशाला के दौरान, प्रतिभागियों ने डीआईएसआई कार्यक्रम को लागू करने में अपने अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। उन्होंने क्षेत्र में इनपुट डीलर्स के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की और इन चुनौतियों से निपटने के तरीकों की पहचान की।

सुविधाकर्ताओं ने इनपुट गुणवत्ता, उत्पाद ज्ञान और ग्राहक सेवा सहित कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

यह कार्यशाला अपने अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए कृषि क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाने में सफल रही। डीआईएसआई कार्यक्रम किसानों को दिए जाने वाले इनपुट की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और कार्यशाला में इसके उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कार्यशाला का समापन प्रतिभागियों की बेहतर समझ और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नई प्रतिबद्धता के साथ किया गया।

अंत में, मध्य प्रदेश में डीआईएसआई कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला प्रतिभागियों के लिए अपने अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का एक मूल्यवान अवसर था।

मैनेज में डॉ. महंतेश शिरूर, उप निदेशक (कृषि विस्तार) और प्रधान समन्वयक, डीआईएसआई ने कार्यशाला का समन्वय किया।



इंटरनशिप कार्यक्रम

बागवानी छात्रों के लिए कृषि-स्टार्टअप



मैनेज ने 18-27 अप्रैल, 2023 के दौरान बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएचएस), बागलकोट के बीएससी अंतिम वर्ष के 30 छात्रों के लिए कृषि-स्टार्टअप और उद्यमिता पर 10-दिवसीय इंटरनशिप-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

इंटरनशिप कार्यक्रम ने छात्रों को छह चयनित कृषि-स्टार्टअप के संस्थापकों और कृषि उद्यमियों से जोड़कर व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया। स्टार्टअप्स में सिड फार्म, एलआर नेचुरल प्रोडक्ट्स, मिलेनोवा फूड्स, कोस्टल फूड्स, फिश फार्मर्स और परीक्षित फूड्स शामिल थे।

इस कार्यक्रम ने छात्रों को अपने व्यवसाय मॉडल में सुधार करने और डिजिटल मीडिया, टीम निर्माण, संचार और नई दक्षताओं पर मूल्यवान ज्ञान प्राप्त करने में मदद की।

छात्रों को स्टार्टअप चलाने के पारिस्थितिकी तंत्र की गहन समझ प्राप्त हुई और उन्हें एक प्रेजेंटेशन, केस स्टडी और फील्ड विजिट पर एक सामान्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ी। कार्यक्रम व्यावहारिक और इंटरैक्टिव था, जिससे छात्रों को काम सीखने का मौका मिला।

मैनेज के निदेशक (कृषि विस्तार) डॉ. सरवणन राज ने कार्यक्रम का समन्वय किया।



प्रतिस्पर्धा कानून और सार्वजनिक खरीद



भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 28 अप्रैल 2023 को मैनेज में मैनेज के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धा कानून और सार्वजनिक खरीद पर एक समर्थन कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा संस्कृति को बढ़ावा देना और निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा नियम लागू करना था।

मैनेज के महानिदेशक डॉ. पी. चंद्रा शेखरा ने अपने उद्घाटन भाषण में सार्वजनिक खरीद से संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डाला और जागरूकता की आवश्यकता और सार्वजनिक खरीद के लिए GeM पोर्टल के उपयोग पर जोर दिया।

कार्यशाला में क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्र आयोजित किए गए, जिनमें श्री पंकज कुमार, निदेशक एफए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली, आर. सी. कुमार, राज्य संसाधन व्यक्ति और वी. प्रसन्ना, राज्य संसाधन व्यक्ति, सीसीआई, तेलंगाना, हैदराबाद शामिल थे।



सत्रों में प्रतिस्पर्धा संस्कृति को बढ़ावा देने और सभी बाजार व्यापारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा नियम लागू करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया।

विशेषज्ञों ने सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता की आवश्यकता और निष्पक्ष और पारदर्शी खरीद प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए GeM पोर्टल के उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच प्रतिस्पर्धा कानून और सार्वजनिक खरीद के बारे में जागरूकता पैदा करने में मैनेज की भूमिका पर भी जोर दिया गया। यह सत्र इंटरैक्टिव था और प्रतिभागियों को प्रश्न पूछने और अपनी शंकाओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान किया गया।

कार्यशाला का संचालन श्री श्रीधर खिस्ते, उप निदेशक (प्रशासन), मैनेज ने किया।

डॉ. जी. जया और डॉ. लक्ष्मी मनोहरी को विदाई

मैनेज ने निदेशक एवं प्रमुख (कृषि संस्थानों की क्षमता निर्माण केंद्र) डॉ. जी. जया और उप निदेशक डॉ. पी. लक्ष्मी मनोहरी को 31 मार्च, 2023 को उनकी सेवानिवृत्ति के सफल समापन पर विदाई दी। मैनेज ने उनको भविष्य के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ होने की शुभकामनाएं दीं। मैनेज के महानिदेशक डॉ. पी. चंद्रा शेखरा ने एक विदाई समारोह में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मैनेज के संकाय, कर्मचारी और सेवानिवृत्त अधिकारियों के परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। मैनेज परिवार उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता है और आशा करता है कि वे अपने ज्ञान और अनुभव से कृषि विस्तार क्षेत्र को प्रेरित और प्रभावित करते रहेंगे।



मानव संसाधन विकास विशेषज्ञ डॉ. जी. जया ने तीन दशकों से अधिक समय तक विभिन्न क्षमताओं में काम किया है और विशेष रूप से भागीदारी दृष्टिकोण, कृषि संस्थागत निर्माण और विस्तार पेशेवरों के क्षमता विकास के क्षेत्रों में उनका योगदान सराहनीय रहा है।



डॉ. पी. लक्ष्मी मनोहरी, एक कृषि विस्तार विशेषज्ञ, के रूप में मैनेज में अपनी सेवा प्रदान की है और विस्तार रणनीतियों, जैविक खेती, कृषि व्यवसाय प्रबंधन और कृषि में सहभागी दत्तक अनुसंधान के क्षेत्रों में बहुत योगदान दिया है।

नये संकाय सदस्य



डॉ. एम. श्रीकांत निदेशक (कृषि व्यवसाय प्रबंध)

डॉ. श्रीकांत ने जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जेएनटीयू), हैदराबाद से प्रबंधन अध्ययन में पीएचडी की है। आपको कृषि बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, माइक्रो फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ट्रेजरी संचालन और ग्रामीण विकास में विशेषज्ञता वाले बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में 22 वर्षों का कार्य अनुभव है। मैनेज में निदेशक (कृषि व्यवसाय प्रबंधन) के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन), एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद; आईआईएम शिलांग में संकाय सदस्य; और एजीएम, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रूप में कार्य किए।

आपके पास राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 26 शोध पत्र, 6 केस स्टडीज, 8 पुस्तकें/पुस्तक अध्याय और सभी प्रमुख समाचार पत्रों में 40 से अधिक लोकप्रिय लेख हैं।

डॉ. के. कृष्णा रेड्डी निदेशक (आईसीटी)

डॉ. कृष्णा रेड्डी ने जस्टस लिबिग यूनिवर्सिटी, गिसेन, जर्मनी से कृषि अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। आपको कृषि अर्थशास्त्र, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण अर्थशास्त्र, जल और भूमि प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन और कृषि प्रौद्योगिकी के उन्नयन में 15 वर्षों का कार्य अनुभव है। मैनेज में निदेशक (आईसीटी) के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई), दिल्ली के लिए भारत में विशेष परियोजना वैज्ञानिक और क्षेत्रीय शोधकर्ता और एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद के रूप में कार्य किए। आपके नाम 28 शोध लेख, 5 पुस्तकें, 17 पुस्तक अध्याय, 7 रिपोर्ट और 4 नीति विवरण हैं।



डॉ. ए. श्रीनिवासचार्युलु उप निदेशक (नॉलेज मैनेजमेंट)

डॉ. ए. श्रीनिवासचार्युलु ने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पीएचडी की है। आपको कृषि सूचना और ज्ञान प्रबंधन, डिजिटल कृषि, डॉक्यूमेंटेशन, संपादन और प्रकाशन, एमओओसी, संचार और आउटरीच और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में 25 वर्षों का अनुभव है। उप निदेशक (ज्ञान प्रबंधन) के रूप में शामिल होने से पहले, उन्होंने मैनेजमेंट कार्यक्रम अधिकारी, अनुसंधान सहयोगी के रूप में कार्य किया; एशिया-पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ एगीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन (APAARI), बैंकॉक, थाईलैंड में कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली के समन्वयक; और सार्क कृषि केंद्र, ढाका, बांग्लादेश में सूचना विशेषज्ञ रहें।

आपके नाम 25 शोध प्रकाशन हैं और आपने 15 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों का समन्वय किया है।



संपादकीय टीम

मैनेज बुलेटिन का प्रकाशक

डॉ. पी.चंद्रा शेखरा, महानिदेशक

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद -500030, भारत.

वेबसाइट: www.manage.gov.in

मैनेज बुलेटिन का प्रकाशक

मुख्य संपादक

डॉ. पी. चंद्रा शेखरा

महानिदेशक, मैनेज

संपादक

डॉ. ए. श्रीनिवासा चार्युलु

प्रोग्राम ऑफिसर, मैनेज

एसोसिएट एडिटर

वीणा पुलपाका

आउटरीच स्पेशलिस्ट, मैनेज

अपर्णा वी. आर., मैनेज फेलो

हिन्दी अनुवाद

डॉ. के. श्रीवल्ली, सहायक निदेशक (रा.)